Note:

1. The above information pertains to General Pool residential accommodation in Delhi wrich is under the control of Ministry of Urban Development.

2. The applicants waiting for allotment as on 30-11-94 referred to at Column No. 4 on pre page is based on limited applications called for in the current Allotment Year 1994-1995.

3. For in turn allotments upto Type-I to IV, the length of service for Government employees is the basic criteria. The officials who join service after the date indicated in Column No. 5 on pre-page are waiting for allotment of accommodation in their turn..

4. For higher types of accommodation viz. Type-IV (Spl.) and above, the allotment are made on the basis of the basic pay drawn by an officer on a particular date.

Attending complaints by CPWD in North Avenue and Ferozeshah Road

615. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the CPWD Enquiry Offices in North Avenue and Ferozeshah Road do not properly attend to complaints of Members of Parliament;

(b) whether it is also a fact that whenever complaints are attended to they are just nominal and for name's sake and not utility oriented.

(c) what measures/steps Government propose to take to check the large scale wastage of Government money by the said offices; and

(d) what action is being contemplated by Government against the erring staff?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P. K. THUNGON): (a) and (b) The CPWD have stated that the complaints received in the Enquiry Offices are being properly attended to. More than 94 percent. of the complaints are being attended within 24 hours after the year received in the two Enquiry

(c) Maintenance of MP's flats and bunglaows is closely monitored and regular meetings are held to review and discuss steps for proper and effective coordination between various agencies involved with such maintenace.

(d) From a feed-back received through the inspection cards from MPs whose bungalows and flats are being maintained by the Enquiry Offices. There do not to be wastage of government

मध्य प्रदेश में गृह निर्माण परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

661. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में विदेशी सहायता से गृह निर्माण परियोजनायें आरंभ कर दी गई ह ;

(ख) यदि हां, तो इस सहायता का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है ;

(ग) किन-किन स्थानों पर अब तक कितने-कितने मकानों का निर्माण किया जा चुका है/विचाराधीन है ;

(घ) निर्माणाधीन मकानों की आवंटन प्रक्रिया के लिए किस प्रणाली को अपनाया गया है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य में कुल कितने मकानों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने बताया है कि जून, 1991 से राज्य में विदेशी सहायता से

कोई आवास परियोजना शुरू नहीं की गई है। तथापि, राज्य सरकार ने राज्य के दस शहरों में अर्ध निर्मित मकान (स्केलटेल हाऊस) बनाने और प्लाटों के विकास के लिए पहले विश्व बैंक की सहायता ली थी। जुलाई, 1983 से जून, 1991 तक कुल 11822 स्केलटेल (अर्ध-निर्मित) मकान और 12852 विकसित प्लाट उपलब्ध कराये गये है।

नगर-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

क्रम सं०	शहर का नाम	निर्मित मकानों की संख्या	विकसित प्लाट	योग
1	इन्दौर	4090	2150	6240
2	उज्जैन	1360	1291	2651
3	देवास	511	284	795
4	रायपुर	2217	1310	3527
5	दुर्ग	671	1100	1771
6	भिलाई	1912	2082	3994
7	शाहवाल	158	504	682
8	खण्ड	272	1604	1876
9	सागर	330	1183	1513
10	रतलाम	301	1344	1645
	योग	11822	12852	24674

(घ) अर्ध निर्मित मकानों और विकसित प्लाटों के आबंटन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई थी :—

(i) आबंटन ड्रा द्वारा।

(ii) पहले से पंजीकृत लाभार्थियों को आबंटन में उच्च प्राथमिकता दी गई।

(iii) लाभार्थि 18 वर्ष से अधिक आय का हो।

(iv) आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो अथवा पांच वर्षो से अधिक समय मध्य प्रदेश में रहा हो।

(v) आवेदक ऐसे मकानों के आबंटन हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आय समह से संबंधित हो।

(vi) विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण।

(vii) आवेदक / उसके परिवार के किसी सदस्य के पास पहले से कोई प्लाट मकान न हो।

(ङ) जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, फिलहाल ऐसा कोई नया प्रस्ताव नहीं है।

Letters Received from MPS

617. SHRI O. P. KOHLI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of letters received from the Members of Parliament by the Minister of Urban Development, Minister of State for Urban Development, Director of Estates, Director General, CPWD in the last three years on matters other